Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
January 2024 5(1), 1047–1052

CHANGING DIMENSIONS OF CASTE AND ELECTORAL POLITICS IN BIHAR

बिहार में जाति और चुनावी राजनीति के बदलते आयाम

Dr. Manish Kumar [1], Dr. Sanjeev Kumar [2]

[1] Associate Professor, Swami Shraddhanand Mahavidyalaya, University of Delhi, India
[2] Assistant Professor, Shyama Prasad Mukherjee Mahavidyalaya, University of Delhi, India

DOI
10.29121/shodhkosh.v5.i1.2024.2627

Funding: This paper is the result of a completed research project "Mapping Electoral Behaviour in Reserved Constituencies: A Study of Bihar Assembly Elections F. No. 02/216/SC/2015-16/RPR" funded by Indian Council of Social Science Research (ICSSR).

Copyright: © 2024 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

ABSTRACT

English: This paper examines the changes in electoral politics in India since independence, particularly focusing on the growing participation of marginalised groups, especially Dalits and Other Backward Classes (OBCs), in the democratic process, particularly in Bihar. Pre-independence electoral politics was dominated by upper class and upper caste leaders, but figures such as Dr. B. R. Ambedkar advocated the political empowerment of the disadvantaged classes. This article divides the evolution of this movement into two main phases: the first, from 1967 to 1990, which focused on the political empowerment of OBCs and Dalits in regions such as Uttar Pradesh and Bihar, with figures such as Karpoori Thakur, Kanshi Ram and Ram Manohar Lohia playing key roles. It also analyses the political volatility of Bihar during this period, including the shift in the balance of power between leading and backward castes, the rise of caste-based activism, and the influence of money and power.

Hindi: यह शोधपत्र स्वतंत्रता के बाद से भारत में चुनावी राजनीति में आए परिवर्तनों की जांच करता है, विशेष रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हाशिए पर पड़े समूहों, खासकर दलितों और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के बढ़ते सहभागिता पर केंद्रित है, विशेष रूप से बिहार में। स्वतंत्रता से पूर्व चुनावी राजनीति पर उच्च वर्ग और उच्च जाति के नेताओं का प्रभुत्व था, लेकिन डॉ. बी. आर. अम्बेडकर जैसी हस्तियों ने वंचित वर्गों के राजनीतिक सशक्तिकरण की वकालत की। यह लेख इस आंदोलन के विकास को दो मुख्य चरणों में विभाजित करता है: पहला, 1967 से 1990 तक, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे क्षेत्रों में ओबीसी और दलितों के राजनीतिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें कर्पूरी ठाकुर, कांशीराम और राम मनोहर लोहिया जैसी हस्तियों की प्रमुख भूमिका रही। इसमें बिहार के उस समय के राजनीतिक अस्थिरता का भी विश्लेषण किया गया है, जिसमें अग्रणी और पिछड़ी जातियों के बीच सत्ता संतुलन में बदलाव, जाति आधारित सक्रियता का उदय और धन और सत्ता का प्रभाव शामिल है।

1. प्रस्तावना

स्वतंत्रता के बाद के भारत में चुनावी राजनीति ने अत्यधिक महत्त्व प्राप्त किया। स्वतंत्रता से पूर्व, राजनीतिक सहभागिता मुख्य रूप से अभिजात वर्ग और प्रभावशाली जातियों के नेताओं तक सीमित थी। हालाँकि, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर जैसी हस्तियों ने निम्न जातियों की राजनीतिक भागीदारी की वकालत की, यह मानते हुए कि सच्चे लोकतंत्र के लिए हाशिए पर पड़े समुदायों की सहभागिता और प्रतिनिधित्व आवश्यक है। अम्बेडकर ने यह स्पष्ट किया कि राजनीतिक लोकतंत्र से पहले सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र आना चाहिए (अम्बेडकर, 1979)। उन्होंने यह भी देखा कि वंचित समूहों का अक्सर ऊँची जातियों द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए शोषण किया जाता था। भारत की स्वतंत्रता और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की स्थापना के बाद, दलित और अन्य हाशिए पर पड़े समुदाय—जो देश की जनसंख्या का लगभग 80% थे—चुनावी प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाने लगे। इसके परिणाम स्वरूप, जाति चुनावी राजनीति में एक केंद्रीय धुरी बन गई। अम्बेडकर ने विशेष रूप से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हाशिए पर पड़े समूहों के बीच सांस्कृतिक एकता की भावना को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हालाँकि उत्तरी भारत में इस तरह के आंदोलनों का उतना प्रभाव नहीं था।

इस संदर्भ में दो महत्वपूर्ण घटनाएँ उभरीं। पहला, दलित पैंथर आंदोलन ने विभिन्न स्तरों पर जाति व्यवस्था को सक्रिय रूप से चुनौती दी (वाडेकर, 2024)। दूसरा, राम मनोहर लोहिया और कांशीराम जैसे नेताओं ने बिहार और उत्तर प्रदेश में दलितों और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को राजनीतिक रूप से संगठित किया, जिससे जाति विरोधी राजनीति की नींव पड़ी (भाट, 2019)। इस राजनीतिक लामबंदी के परिणाम स्वरूप बिहार में ओबीसी की चुनावी प्रमुखता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। विद्वानों ने जाति और चुनावी व्यवहार के विकास का विश्लेषण दो अलग-अलग चरणों में किया है।

2. प्रथम चरण: 1967-1990

1967 से 1975 में आपातकाल तक, बिहार में गंभीर राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिली। 1960 के दशक की शुरुआत तक, अग्रणी जातियों का पारंपरिक भूमि पर नियंत्रण कमजोर होने लगा था, जिससे ऊपरी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसे यादव, कोइरी और कुर्मी सामाजिक-आर्थिक सुधारों की मांग करने लगे और बदलाव के वाहक के रूप में उभरने लगे। 1968 तक ये पिछड़ी जातियाँ अपने सामाजिक-आर्थिक अधिकारों के प्रति "अधिक मुखर" होने लगी थीं (जुन्नूज़ी, 1974)।

अग्रणी जातियाँ, जो "मुख्य रूप से कांग्रेस के साथ संबद्ध थीं," इन उभरते समूहों के साथ राजनीतिक सत्ता साझा करने का विरोध कर रही थीं। पिछड़ी जातियों के लिए सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण की समाजवादी मांग ने ओबीसी समुदायों को और भी उत्साहित किया। इसके बावजूद, निचले ओबीसी और अनुसूचित जातियाँ (एससी) बड़े पैमाने पर वंचित रहीं और अक्सर "भूमिहीन या ऐसे किरायेदार के रूप में काम करती थीं जो जमींदारों और नए भूस्वामियों पर निर्भर थे।" इस बीच, जैसे-जैसे भूमि स्वामित्व वाली अग्रणी जातियों और बढ़ती शक्ति वाले यादवों के बीच सत्ता का संघर्ष जारी रहा, "वे निचले ओबीसी और बीसी के खिलाफ एकजुट हो गए" (झा, 1970)।

1967 के चुनावों के बाद, जन संघ, कम्युनिस्टों और संयुक्त समाजवादी पार्टी (एसएसपी) सहित विपक्षी दलों ने मिलकर संयुक्त विधायक दल (एसवीडी) नामक गठबंधन बनाया। इस राजनीतिक गठबंधन के परिणाम स्वरूप, महामाया प्रसाद सिन्हा, जो पूर्व कांग्रेस सदस्य थे, बिहार के पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने, जबकि कर्पूरी ठाकुर को उपमुख्यमंत्री बनाया गया। इस गठबंधन के सफल प्रयोग का विस्तार उत्तर प्रदेश तक भी हुआ। चौधरी चरण सिंह का कांग्रेस से अलग होना और उनके किसान राजनीति में संलग्न होना ओबीसी राजनीतिक लामबंदी को और भी मजबूत बना गया।

हालांकि, एसवीडी सरकार अल्पकालिक साबित हुई। सतीश प्रसाद सिन्हा ने थोड़े समय के लिए सत्ता संभाली, लेकिन जल्द ही उन्हें बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने प्रतिस्थापित कर दिया, जिन्होंने 40 निम्न जाति के विधायकों के समर्थन से शोषित दल (एसडी) की स्थापना की। इसके बाद, पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री बिनोदनंद झा और एक दलित विधायकों के समूह ने लोकतांत्रिक कांग्रेस दल (एलटीसी) का गठन किया, जिससे भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री बने। फिर भी, उनकी सरकार, इस अवधि की कई अन्य सरकारों की तरह, जल्दी ही गिर गई और राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया।

1969 के चुनावों में त्रिशंकु विधानसभा बनी। हरिहर प्रसाद सिंह पहले ओबीसी मुख्यमंत्री बने, हालांकि उनका कार्यकाल चार महीने से भी कम समय तक चला। भोला पासवान शास्त्री एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार भी दो हफ्ते के भीतर गिर गई, जिससे एक और राष्ट्रपति शासन का दौर शुरू हो गया। 1970 में, कांग्रेस ने यादव नेता दरोगा प्रसाद राय को मुख्यमंत्री नियुक्त किया, लेकिन पार्टी के अंदरूनी गुटबाज़ी के कारण जल्द ही उनकी जगह एक अग्रणी जाति के उम्मीदवार ने ले ली। अंततः, कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने जब एकजुट विपक्ष ने कांग्रेस को सफलता पूर्वक सत्ता से बेदखल कर दिया। हालांकि पिछड़ी जातियों का पूर्ण संगठित होना अभी तक साकार नहीं हुआ था, इस राजनीतिक अस्थिरता के दौर ने बिहार की सत्ता संरचना में संभावित बदलाव की ओर संकेत दिया। इस बीच, कांग्रेस में असंतोष बढ़ता गया, जिसका प्रमाण नेतृत्व में बार-बार परिवर्तन और राज्यपाल शासन के बार-बार लागू होने से मिला।

जैसा कि कचरू ने देखा, "1960 के दशक के अंत की राजनीतिक अस्थिरता का अंततः लाभ कांग्रेस को हुआ, जिसने 1972 में केदार पांडे के नेतृत्व में सत्ता फिर से हासिल की। हालांकि, यह अब वह प्रभावशाली पार्टी नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी; जयप्रकाश नारायण (जेपी) के नेतृत्व में कांग्रेस विरोधी भावना बढ़ी, जिससे पिछड़ी जातियों का व्यापक राजनीतिक लामबंदी हुई। आपातकाल के बाद, 1977 के चुनावों में जनता पार्टी ने भारी जीत हासिल की, और कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने। इस दौरान, बिहार विधानसभा में अग्रणी जातियों का प्रतिनिधित्व 1967 में 55.1% से घटकर 1977 में 48.6% हो गया, जबकि पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व 34.5% से बढ़कर 38.5% हो गया" (कचरू और कचरू, 1999)। हालांकि ऊँची जातियाँ, विशेष रूप से ब्राह्मण, कुछ प्रभाव बनाए रखने में सफल रहीं, लेकिन उनके पतन ने यादवों और अन्य ओबीसी को अधिक राजनीतिक प्रमुखता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। पुष्पेंद्र ने उल्लेख किया कि कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में पिछड़ी जातियों ने मंत्रिमंडल में बहुमत हासिल कर लिया, जिससे जनता पार्टी के भीतर सत्ता संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव आया।

पिछड़ी जातियों के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव के बावजूद, कई गंभीर चुनौतियाँ बनी रहीं। सिंह ने भूमि सुधार की अत्यावश्यकता पर बल दिया, लेकिन सरकार को अग्रणी जातियों के समूहों से भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिससे राजनीतिक अस्थिरता जारी रही। अग्रणी जातियों के विधायकों के बीच असंतोष और जनता पार्टी के भीतर गहरे विभाजन ने एक अस्थिर राजनीतिक माहौल तैयार किया। यद्यपि केंद्र में जनता सरकार अपेक्षाकृत कम समय तक चली, उसने मंडल आयोग की स्थापना की, जिसने पिछड़ी जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की जांच का प्रयास किया। आयोग की रिपोर्ट, जिसने मजबूत आरक्षण की सिफारिश की, भारत में जाति पर व्यापक बहस को जन्म दिया और पूरे देश में जातिगत चेतना को बढ़ाया।

1980 के दशक में कांग्रेस को घटते समर्थन और आंतरिक गुटबाज़ी से जूझना पड़ा। जैसा कि साहा ने देखा, सांप्रदायिक दंगों के बाद कांग्रेस ने मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा खो दिया, जबकि अग्रणी जातियों के मतदाता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जैसी उभरती पार्टियों की ओर झुकने लगे। कांग्रेस के भीतर आंतरिक विभाजन ने उसकी स्थिरता और नेतृत्व को और कमजोर कर दिया।

माथुर के अनुसार, "1980 के दशक को आर्थिक गिरावट और बढ़ती बेरोजगारी के रूप में चिह्नित किया गया। बिहार का कृषि क्षेत्र ठहराव में था, और औद्योगिक विकास में भी गिरावट आई। इस अवधि के अंत तक, कांग्रेस को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो नई राजनीतिक संरचनाओं के उभरने का संकेत था" (माथुर, 1994)। आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता के इस दौर ने उन नए राजनीतिक आंदोलनों के उदय का संकेत दिया, जो राज्य के चुनावी परिदृश्य को बदलने वाले थे।

3. द्वितीय चरण: पोस्ट-1990

द्वितीय चरण में, "जाति बिहार में राजनीतिक विमर्श पर हावी बनी रहती है, पार्टी समर्थन को प्रभावित करती है। झा ने पुष्टि की कि बिहार का राजनीतिक इतिहास जातीय गठबंधनों और लामबंदियों से भरा हुआ है। 1990 के दशक में कांग्रेस प्रणाली का पूरी तरह से पतन हुआ, साथ ही राजनीतिक अभिजात वर्ग का परिवर्तन ऊँची जातियों से पिछड़ी जातियों की ओर हुआ" (उल्लेख & मिश्रा, 2013)।

"1978 में मंगरिलाल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन, जो पिछड़ी जातियों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए थी, ने व्यापक दंगों को भड़काया और अंततः कर्पूरी ठाकुर की सरकार के गिरने का कारण बना। इस अवधि में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी और रामविलास पासवान जैसे प्रभावशाली नेताओं का उदय भी देखा गया" (अहमद, 2010)।

"1990 के दशक ने एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, क्योंकि मंडल आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन ने समर्थक और विरोधी आरक्षण गुटों के बीच हिंसक झड़पों को जन्म दिया, जिससे जातिगत तनाव बढ़ गया। इस दौरान, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों आरक्षण राजनीति के मजबूत समर्थक के रूप में उभरे। एक लोकतंत्र में जो आधुनिक कानूनी और राजनीतिक प्रणालियों से आकारित है, जाति, आश्चर्यजनक रूप से, हाशिए पर रहे समूहों के लिए सामाजिक, राजनीतिक, और आर्थिक संसाधनों तक पहुँचने का एक महत्वपूर्ण तंत्र बन गई है। नेहरू का एक आधुनिक भारत का दृष्टिकोण, जहाँ जाति के लिए लोकतांत्रिक राजनीति में कोई स्थान नहीं होगा, यह दर्शाता है कि 'उदारवादी' लोकतंत्र सामाजिक पदानुक्रमों को समाप्त करने में असफल रहा है। आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में जाति की भूमिकाओं का तेजी से विकास 'जाति सामाजिक' और 'जाति राजनीतिक' के बीच एक बारीक विभाजन की मांग करता है" (कुमार, 1999)।

"जाति सामाजिक" का तात्पर्य प्राचीन और मध्यकालीन समय में स्थापित पारंपरिक पदानुक्रमों से है, जिसने एक कठोर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक, जाति और वर्ग के बीच का अंतर धीरे-धीरे धुंधला होता गया। जाति का यह पहलू छूआछूत और आर्थिक निर्भरता जैसी प्रथाओं से चिह्नित था, जिससे हाशिए पर रहे समूहों के लिए सामाजिक गतिशीलता लगभग असंभव हो गई। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, जो मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी द्वारा संचालित था, हाशिए पर रहे समुदायों से कुछ ही नेताओं ने शोहरत प्राप्त की, जबकि व्यापक निम्न जाति की जनसंख्या कृषि श्रम या ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रदर्शनों में कड़ी नियंत्रण में रही। जबकि "जाति सामाजिक" ने ऊँची जातियों की प्रथाओं की नकल करने के प्रयासों के माध्यम से असहमति व्यक्त की (जिसे संस्कृतकरण के रूप में जाना जाता है), भूमि और मजदूरी अधिकारों के केंद्रित आंदोलनों ने मूल सामाजिक पदानुक्रम को बदलने में शायद ही कोई सफलता प्राप्त की, जो ऊँची जाति के जमींदारों द्वारा ही नियंत्रित रहा" (झा & पुष्पेंद्र, 2012)।

1990 के दशक में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ जब "जाति सामाजिक" "जाति राजनीतिक" में विकसित हुई। "जाति एक राजनीतिक पहचान के रूप में उभरी, जिससे आर्थिक नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से राजनीतिक शक्ति की खोज संभव हो गई। इस परिवर्तन ने राजनीतिक कार्यालयों में अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के प्रतिनिधित्व में उल्लेखनीय वृद्धि की, विशेष रूप से यादवों, कुर्मियों और कोरियों जैसे समूहों में, जो ऊँची जातियों के प्रतिनिधित्व को पीछे छोड़ दिया। इस प्रकार जाति राजनीतिक आत्म-प्रकाशन का एक शक्तिशाली वाहन बन गई" (झा & पुष्पेंद्र, 2012)।

इस राजनीतिक सशक्तिकरण का सामाजिक गतिशीलता पर व्यापक प्रभाव पड़ा। "जबकि वर्ग संघर्ष स्वाभाविक रूप से जटिल होते हैं, जाति राजनीतिक लामबंदी के लिए एक अधिक सरल उपकरण बन गई। 'जाति राजनीतिक' वर्ग के भीतर जाति गतिशीलता पर जोर देती है, ऊँची जातियों के चुनावों में प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए जाति-आधारित संघर्षों को बढ़ावा देती है। इस संघर्ष में इज्जत (सम्मान) की अवधारणा केंद्रीय बन गई। राजनीतिक जाति ने पारंपरिक पदानुक्रमों से ध्यान हटा कर संसाधनों पर प्रभुत्व और नियंत्रण की आकांक्षाओं पर केंद्रित किया। इस विकास ने शास्त्रीय जाति प्रणालियों के महत्व को कम किया, जिससे निम्न जातियों की गर्व और महत्वाकांक्षाओं की ओर ध्यान केंद्रित हुआ" (कुमार, 1999)।

1980 के दशक तक, पिछड़ी जातियों की राजनीति में महत्व का उतार-चढ़ाव होता रहा। "1980 के प्रारंभ तक, पिछड़ी जातियों के बीच समृद्ध किसानों (कुलाकों) की एक नई श्रेणी उभरने लगी। जो राजनीतिक दल उनकी महत्वता को पहचानने में विफल रहे, उन्हें चुनावी परिणामों का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी, विशेष रूप से, पिछड़ी जातियों को शामिल करने वाले एक गठबंधन का निर्माण करने में संघर्ष कर रही थी। इसके पीछे कई कारण थे: 1990 तक, पार्टी ने ऊँची जातियों और जमींदार अभिजात वर्ग के साथ एक गठबंधन बनाए रखा, जिसका कोई चुनौती नहीं थी; शुरुआती चुनावों में बहुत कम विपक्ष था; और समाजवादी आंदोलन सक्रिय रूप से ओबीसी समर्थन की ओर आकर्षित हो रहे थे" (कुमार, 1999)।

1990 में कांग्रेस पार्टी की हार बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित करती है, जिसे "फ्यूडल लोकतंत्र" के रूप में वर्णित किया गया। "पार्टी ने भूमि सुधार और सामाजिक न्याय जैसे स्वतंत्रता के बाद के वादों को पूरा करने में विफलता दिखाई, और मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का विकल्प चुना" (झा & पुष्पेंद्र, 2012)। 1980 के दशक में "भूमि सेना" जैसी निजी जाति मिलिशियाओं का उदय देखा गया, जो नक्सलवादी आंदोलन का मुकाबला करने और हाशिए पर रहे श्रमिकों और किसानों को लामबंद करने के लिए उभरी। गुप्ता ने बताया कि ये मिलिशियाएँ, जो अक्सर राज्य प्राधिकरणों द्वारा समर्थित होती थीं, निम्न जाति के समुदायों के खिलाफ आतंक करती थीं। सरकारी अस्थिरता, भ्रष्टाचार, और सामाजिक अशांति ने कांग्रेस को जनता से और अधिक अलग कर दिया" (गुप्ता, 2001)।

1990 में लालू प्रसाद यादव के तहत जनता दल का गठन पिछड़ी जातियों, विशेष रूप से ओबीसी, मुसलमानों और कुछ राजपूतों और दलितों के बीच एकजुटता का प्रतीक था। "मुख्य ओबीसी समूह—यादव, कुर्मी और कोरी—इस गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, लेकिन आंतरिक विभाजन तेजी से उभरे, विशेष रूप से समता पार्टी के गठन के बाद, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक न्याय के एजेंडे में विभाजन हो गया" (आलम, 2014)। हालांकि लालू प्रसाद यादव का जनता दल 1991 के चुनावों में सफल रहा, लेकिन पिछड़ी जातियों के बीच एकता नाजुक साबित हुई। "संसाधनों के लिए आपसी लड़ाई और पक्षपात ने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले गुटों के बीच विभाजन का कारण बना, जिससे गठबंधन कमजोर हुआ" (कुमार, 1999)। "जबकि लालू प्रसाद का जनता दल 1995 के विधानसभा चुनावों में एक महत्वपूर्ण बहुमत हासिल करने में सफल रहा, चुनावी प्रतिस्पर्धा एक अग्रिम-पिछड़े गतिशीलता से अलग-अलग पिछड़ी जाति समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा में बदल गई" (कुमार, 2014)।

1990 के दशक में कांग्रेस पार्टी के प्रभाव में महत्वपूर्ण गिरावट ने अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के राजनीतिक सशक्तिकरण को जन्म दिया। "इस अवधि के बाद, ओबीसी का प्रतिनिधित्व विधानसभाओं में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा, विशेष रूप से यादव समुदाय के बीच, जो एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। अपने पहले कार्यकाल के दौरान, लालू प्रसाद यादव ने न केवल राजनीतिक स्थिरता लायी, बल्कि साम्प्रदायिक शांति भी बनाए रखी, जो कांग्रेस शासन के दौरान हुई बार-बार दंगों के विपरीत थी। अल्पसंख्यकों और हाशिए पर रहे समूहों के लिए सुरक्षा एक प्राथमिक चिंता थी, जो बिजली, सड़कों और पेयजल जैसे मुद्दों को फीका करती थी। लालू की प्रशासन ने साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने में सफलता प्राप्त की, जिससे पिछड़ी जातियों और दलितों के घरों की सुरक्षा सुनिश्चित की। इससे इन समुदायों के बीच एक सुरक्षा और आशा की भावना बनी, कि बिहार अधिक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण बनेगा" (झा & पुष्पेंद्र, 2012)। जबकि लालू प्रसाद ने महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्थिरता हासिल की, "उन्होंने बुनियादी ढांचे, पेंशन और गरीबों की बुनियादी जरूरतों से संबंधित वादों को पूरा करने में विफलता दिखाई। उनकी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल (राजद), 1996 और 1999 के लोकसभा चुनावों में लोकप्रियता में गिरावट देखी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और समता पार्टी ने मजबूती से कदम रखा। लालू के दूसरे कार्यकाल के अंत तक, अपहरण और जबरन वसूली जैसे मुद्दों में वृद्धि हो रही थी, साथ ही 'यादवीकरण' की प्रवृत्ति भी थी, जहां लालू ने अपनी जाति और पार्टी के समर्थकों के हितों को प्राथमिकता दी" (हॉसर, 1997)।

"चारा घोटाले का खुलासा लालू प्रसाद को संदिग्ध बना दिया, जिसके परिणामस्वरूप उन पर भारी राजनीतिक दबाव आया और उनके इस्तीफे की मांग की गई" (कुमार, 2014)। इससे उन्हें जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने और अपनी पार्टी, राजद (आरजेडी), बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। "ओबीसी मतदाताओं ने मुख्यतः भाजपा, जद (यू) और राजद का समर्थन किया, जबकि पिछड़ी जातियों में विभाजन ने नए सामाजिक और राजनीतिक गठबंधनों को जन्म दिया" (आलम, 2014)।

"नीतीश कुमार ने 1995 के विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा के साथ एक गठबंधन बनाया। इस गठबंधन का उद्देश्य, भले ही उनके विचारधाराओं में भिन्नता थी, आरजेडी के 'जंगल राज' के खिलाफ 'विकास' और 'अच्छी शासन' का एक एकीकृत मोर्चा प्रस्तुत करना था। हालांकि यह गठबंधन 2000 में सरकार बनाने में शुरू में संघर्ष करता रहा, फिर भी आरजेडी ने अपने सबसे अधिक ओबीसी वोट प्राप्त किए। इसके विपरीत, बाद के चुनावों में, आरजेडी को महत्वपूर्ण नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसमें यादव समुदाय से समर्थन में उल्लेखनीय कमी आई, खासकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में अन्य पार्टियों के उदय के कारण" (जगन्नाथन, 2013)। बिहार चुनाव अध्ययन (2000) ने संकेत दिया कि समता पार्टी, हालांकि शुरू में कमजोर थी, अंततः भाजपा के साथ एक पूर्व-चुनावी गठबंधन बनाते हुए बहुत सारे सीटें जीतीं। हालांकि, जब नीतीश कुमार चुनावों के बाद बहुमत समर्थन साबित करने में विफल रहे, तो लालू प्रसाद को फिर से नेतृत्व करने का एक और अवसर मिला, हालाँकि उन्हें जल्द ही चारा घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा।

2004 के लोकसभा चुनावों में, आरजेडी की सफलता को लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) और कांग्रेस के साथ रणनीतिक गठबंधन के लिए श्रेय दिया जा सकता है, जिसने मुस्लिमों और यादवों के साझा मतदाता आधार का लाभ उठाया, जिससे वे चुनावी परिदृश्य पर हावी हो गए। फिर भी, 2005 के विधानसभा चुनावों में, आरजेडी के भीतर आंतरिक प्रतिद्वंद्विता ने इसकी सीटों की संख्या में गिरावट का कारण बना, जबकि जद (यू) ने विशेष रूप से कुर्मी और कोरी मतदाताओं के बीच महत्वपूर्ण लाभ हासिल किया। "नीतीश कुमार के तहत ऊपरी जातियों के पुनरुत्थान ने राजनीतिक परिदृश्य को जटिल बना दिया। नीतीश ने 'अच्छी शासन' के समर्थक के रूप में खुद को कुशलतापूर्वक पेश किया, अपनी प्रशासन को पिछले आरजेडी शासन से दूर करते हुए, जबकि अपने शासन में विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। उन्होंने पिछड़ी मुस्लिम समुदायों के लाभ के लिए नीतियाँ भी शुरू कीं, जिसने उनके समर्थन को मजबूत किया" (कुमार, 1999)। नीतीश कुमार के प्रशासन ने कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ी। उनके उल्लेखनीय उपलब्धियों में नालंदा विश्वविद्यालय की बहाली, महादलित आयोग की स्थापना, सूचना कॉल सेंटर की स्थापना, और स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू करना शामिल था।

2014 के लोकसभा चुनावों के बाद, कुमार का जितेन राम मांझी को मुख्यमंत्री के रूप में समर्थन देना उल्टा पड़ गया, जिसके परिणामस्वरूप मांझी को पद से हटाया गया। 2015 के विधानसभा चुनावों में, कुमार ने भाजपा के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया। इस गठबंधन ने महत्वपूर्ण चुनावी सफलता हासिल की, जिसके परिणामस्वरूप कुमार मुख्यमंत्री के रूप में लौट आए, हालांकि बाद में उन्होंने आरजेडी नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच भाजपा के साथ गठबंधन बदल लिया। कुल मिलाकर, बिहार में जाति राजनीति के गतिशीलता में काफी परिवर्तन आया है, जो बदलती गठबंधनों, मतदाता आधार, और नेतृत्व रणनीतियों द्वारा आकारित हो रहा है, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को निरंतर प्रभावित कर रहे हैं।

दूसरे शब्दों में, "बिहार के भविष्य के राजनीतिक परिदृश्य को केवल 'विकास राजनीति' के उदय पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी हाशिए पर रहने वाले वर्गों और जातियों के बीच एक मजबूत गठबंधन की संभावनाओं पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा गठबंधन उन लोगों के समायोजन के दृष्टिकोण को चुनौती देगा जो पिछले सामाजिक और कृषि अशांति के चक्रों से लाभान्वित हो रहे हैं। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे नेताओं के लिए महत्वपूर्ण समर्थन के साथ, 'उपकेंद्र पुनरुत्थान' ने एक नए चरण में प्रवेश किया है, फिर भी बुनियादी विरोधाभास गहराई से अंतर्निहित हैं" (गुप्ता, 2001)। बिहार की स्थिति यह महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियाँ प्रदान करती है कि कैसे नवउदारवादी विकास को भारत में जाति और वर्ग राजनीति की जटिल गतिशीलता के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है और पुनः आकारित किया जा सकता है। गुप्ता आगे बताते हैं कि "जबकि नीतीश कुमार के विकास के प्रति पहले के दृष्टिकोण ने अपने विरोधाभासों का सामना किया है, बिहार में 'विकास राजनीति' के चारों ओर की दुविधाएँ संभवतः बनी रहेंगी। चुनावी जनादेश स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास को सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों को शामिल करना चाहिए, जिसके लिए ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो विभिन्न जातियों और वर्गों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करें" (गुप्ता, 2001)।

हाशिए पर रहने वाले समूहों, जिसमें दलित, भूमिहीन व्यक्ति, महिलाएँ और पिछड़ी जातियाँ शामिल हैं, ने महागठबंधन का समर्थन किया, जिससे लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) जैसी पार्टियों की हार हुई, जो दलित हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती थीं। उन क्षेत्रों में जहां उग्र वामपंथी विकल्प मौजूद हैं, इन समूहों ने अक्सर ऐसी पार्टियों को वोट दिया है, जो सामाजिक न्याय की मांग को दर्शाती है, जो केवल शब्दों तक सीमित नहीं है।

चुनाव परिणाम भारतीय लोकतंत्र की राजनीतिक और वैचारिक सहनशीलता को भी उजागर करते हैं। बिहार के मतदाताओं, विशेषकर भूमिहीन और दलित समुदायों ने एक ऐसे विकल्प का चयन किया है जो अपने जटिल इतिहास के बावजूद, सामाजिक न्याय और विकास का प्रतिनिधित्व करता है। यह बदलाव उस पारंपरिक कथा को चुनौती देता है जो जाति को विकास से अलग करती है। इन चुनावी परिणामों के महत्व और जटिलता को पूरी तरह से समझने के लिए, शैक्षिक, विद्वान, राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी, और मीडिया के लिए 'जाति' और 'विकास' के बीच अंतःक्रिया की आलोचनात्मक समीक्षा करना आवश्यक है।

2019 से 2024 के बीच बिहार की चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जो जाति संबंधों, गठबंधन निर्माण की रणनीतियों, और नई उभरती राजनीतिक पार्टियों के बीच जटिल अंतःक्रियाओं से आकारित हुए। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और इसके क्षेत्रीय सहयोगी जनता दल (यूनाइटेड) ने राज्य पर नियंत्रण बनाए रखा और 2019 के लोकसभा चुनावों में अधिकांश सीटें जीतीं। नीतीश कुमार, JD(U) के नेता और लंबे समय से मुख्यमंत्री, इस राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी बने रहे। हालांकि, 2020 के बिहार विधान सभा चुनावों में एक बदलाव आया। जबकि एनडीए ने सत्ता बनाए रखी, भाजपा ने गठबंधन के भीतर प्रमुख बल के रूप में उभरते हुए, JD(U) से अधिक सीटें जीतकर शक्ति संतुलन को बदल दिया।

CONFLICT OF INTERESTS

None.

ACKNOWLEDGMENTS

None.

REFERENCES

Ahmad, S. (2010). Nitish's victory: caste in a different mould. TwoCircles.net. http://twocircles.net/2010nov27/nitish%E2%80%99svictory_castedifferentmould.html#.VYvcfRuqqko

Alam, S. (2014). Modi wave or the end of the politics of social justice. Panjab University Research Journal: Social Sciences, 22(2), 192–200.

Ambedkar, B. R. (1979). Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches.

Bhatt, A. (2019). Caste politics in India: with special reference to Uttar Pradesh. OPAL Latrobe University. https://doi.org/10.31124/advance.8068631.v1

Blair, H. W. (1980). Rising kulaks and backward castes in Bihar. Economic and Political Weekly, 15(2).

Fraenkel, F. (1989). Caste, land and domination in Bihar. In F. Fraenkel and M. S. Rao (eds.), Domination and state power in modern India: the collapse of a social order (pp. 29–54). Princeton University Press.

Gupta, S. (2001). New panchayats and subaltern resurgence. Economic and Political Weekly, 36(29), 2742–2744. http://www.epw.in/commentary/bihar-new-panchayats-and-subaltern-resurgence.html

Hauser, W. (1997). The 1996 general elections in Bihar: politics, administrative atrophy, and chaos. Economic and Political Weekly, 32(41).

Jagannathan, R. (2013). Why the BJP-JDU split will be good for India. Firstpost. http://www.firstpost.com/politics/why-a-bjp-jdu-split-will-be-good-for-india-867775.html

Januzzi, F. T. (1974). Agrarian Crisis in India: The Case of Bihar. Sangam Books.

Jha, M. K., & Pushpendra. (2012). The Governance of Caste and the Management of Conflicts: Bihar, 1990–2011. Mahanirban Kolkata Research Group. http://www.mcrg.ac.in/PP48.pdf

Jha, S. N. (1970). Caste in Bihar Politics. Economic and Political Weekly, 5(7).

Kachroo, J. L., & Kachroo, V. (1999). General Sociology. Cosmos BookHive Pvt. Ltd.

Kumar, S. (1999). A New Phase of Backward Caste Politics in Bihar: The Decline of the Janata Dal. Economic and Political Weekly, 34(34-35), 2472–2480.

Kumar, S. (2014). BJP forges a new social coalition in Bihar. Economic and Political Weekly, 44(39), 95–98.

Kumar, S. (2014). Coalition Politics in Bihar. In: E. Sreedharan (ed.), Coalition Politics in India: Selected Issues of Centre and State (pp. 173–208). Academic Foundation.

Kumar, S. (2014). Politics of Bihar: Is there a shift from caste to development? In: M. K. Jha & Pushpendra (eds.), Politics of Bihar: Politics of Development and Social Justice (pp. 212–244). Orient Blackswan.

Mathur, A. K. (1994). Regional Economic Development and Policy. In: G. K. Chaddha (ed.), Policy Approaches in Indian Economic Development. Har-Anand Publications.

Sinha, A. (1996). Social Movements in Bihar: Administrative Feudalism and Distributive Justice. Economic and Political Weekly, 31(51).

Tugvi, K. (2024, May 4). Disha Wadekar | Black Panthers and Dalit Panthers – Cooperationism 13/13. Columbia University. https://cooperism.law.columbia.edu/disha-wadekar-black-panthers-and-dalit-panthers/

Ullekh, N. P., & Mishra, A. K. (2013, July 11). Caste remains an integral part of Bihar's political landscape. The Economic Times. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-07-11/news/40514852_1_caste-calculus-ruling-janata-dal-bihar